सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रशासनिक पदों का रिक्त पड़ा होना

1845. **श्री राम जेठमलानी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के 91 उपक्रमों में सर्वोच्च प्रशासनिक पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सर्वोच्च पद मार्च, 1997 के दौरान नियुक्ति रहित थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि ये पद गत एक वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम कौन कौन से हैं और इन पदों के रिक्त रहने के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): (क) 31.3.1997 तक सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में मुख्य कार्यपालकों के 31 पद रिक्त पड़े थे।

(ख) इन उपक्रमों के नाम विवरण-I में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**।

(ग) इनमें से 11 पद 31.3.1997 तक एक साल से अधिक अवधि से रिक्त पड़े थे।

(घ) इन सरकारी उपक्रमों के नाम विवरण-II में दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**। सरकारी उपक्रमों में निदेशक मण्डल स्तर के पद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरे जाते हैं जिसमें सरकारी उद्यम चयन मण्डल द्वारा चयन, विभिन्न औपचारिकताओं की पूर्ति यथा, सतर्कता अनुमति तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन आदि शामिल हैं।

विवरण-I

उन सरकारी उपक्रमों के नाम जिनमें मुख्य कार्यपालक के पद 31.3.97 से रिक्त पड़े थे

1. भारत भारी उद्योग निगम लि.
2. पावर ग्रिड कारपो. लि.
3. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
4. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
5. टायर कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
6. भारतीय रेलवे वित्त निगम लि.
7. रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनामिक सर्विसिस लि.
8. मझगांव डॉक लि.
9. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.
10. कोल इण्डिया लि. (सहायक कंपनी)
11. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.
12. रेरोल बर्न लि.
13. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.
14. एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इण्डिया लि.
15. स्पंज आयरन इण्डिया लि.
16. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
17. हिन्दुस्तान न्यूजीप्रिंट लि.
18. इण्डियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
19. नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि.
20. फैरो स्क्रेप निगम लि.
21. हिन्दुस्तान फ्लूरोकार्बन्स लि.
22. कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि.
23. ब्रिटिश इण्डिया कारपो. लि.
24. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
25. मद्रास रिफाइनरीज लि.
26. बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लि.
27. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यु. कंपनी लि.
28. हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम लि.
29. उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम
30. जूट कारपो. ऑफ इण्डिया लि.
31. उड़ीसा ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.

विवरण-II

उन सरकारी उपक्रमों के नाम जिनमें 31.3.1997 तक मुख्य कार्यपालक के पद एक वर्ष से अधिक की अवधि से रिक्त पड़े थे।

1. भारत भारी उद्योग निगम लि.
2. पावर ग्रिड कारपोरेशन लि.
3. हिन्दुस्तान कॉपर लि.
4. टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
5. इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपो. लि.

6. रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकानॉमिक सर्विसेज लि.
7. रेरौल बर्न लि.
8. कुद्रेमुख आयरन ओर कं. लि.
9. ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.
10. हिन्दुस्तान फोटोफिल्मस मैन्यु. कं. लि.
11. हैंडीक्राफ्टस एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्टस कारपोरेशन लि.

मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति

3846. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य-प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति करने की कोई व्यवस्था है;

(ख) क्या आयोडीनयुक्त नमक के रियायती दरों पर वितरण के लिए कोई अनुदान/सहायता दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार की आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति करने के लिए कोई वित्तीय सहायता दिए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी बहुल जिलों सहित राज्य के सभी जिलों को आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति करने की व्यवस्था कर रही है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय आयोडीन कमी बिकार नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को आयोडीन कमी विकार (आई डी डी) कक्ष, आई डी डी मानीटरिंग प्रयोगशालाएं, गलगंड/आई डी डी सर्वेक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा आदि की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

Promotion of SSIs in Madhya Pradesh

3847. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are implementing any schemes for promoting Small Scale Industries (SSI) sector in Madhya Pradesh;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have noticed any improvement in the SSI sector in the State after implementing these schemes; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) The development of Small Scale Industries (SSIs) is primarily the responsibility of State Government. The Central Government sets out the policy framework for promotion and development of SSIs. It also renders support services by way of consultancy, technical services, creation of infrastructural facilities, training and entrepreneurship development, etc. The Small Industries Service Institute, Indore (a field office of Small Industries Development Organisation) provides training, technical consultancy and other services to the existing and prospective entrepreneurs in the State. Two Integrated Infrastructural Development Projects have been sanctioned by the Government one in December, 1995 in District Satna and second in May, 1997 in District Seoni of Madhya Pradesh. The other scheme being operated in Madhya Pradesh are Indo-German Tool Room, Indore. The State Government is also providing assistance to the SSIs in the form of Investment Subsidy, Power Subsidy, Reimbursement of the cost of preparation of project reports, concessions regarding Sales Tax and concessions on Entry Tax.

(c) and (d) Yes, Sir. The number of registered SSI units in the State of Madhya Pradesh has shown significant increase and their number has increased from 1,72,545 in 1991 to 2,63,679 in 1996 (Provisional).

Joint venture by Ford Motor Company

3848. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ford Motor Company has submitted a proposal for the setting up of a new joint venture company to be called Automotive Components India (P) Limited;

(b) if so, the details thereof including equity participation in the venture; and

(c) the action Government have taken thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) A proposal was received from M/s. Ford Motor Company USA for setting up a joint venture in India in the name and style of Automotive Components India (P) Ltd., to manufacture auto-components